

कार्यालय-जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

क्रमांक : प-जि.न्याया./लेखा/नवीन क्रय/फर्नीचर/2026-27/268

दिनांक 22/05/2026

एस. आर. प्रारूप-14

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 01/2026-27

[राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 का नियम-43(1) व (2) सपठित 43(5)]

(NIB No. CJK2627A0001)

कोटा न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालयों अतिरिक्त सिविल न्यायालय एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा, एवं सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला कोटा के उपयोग हेतु निम्नवत विगत की विषयवस्तु/सामान/मेटेरियल राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-15 के अन्तर्गत खुली बोली प्रक्रिया से क्रय करने हेतु विनिर्माताओं, प्राधिकृत वितरक एवं विक्रेता/प्राधिकृत स्टॉकिस्ट/प्राधिकृत व्यवहारी/प्राधिकृत सेवा केन्द्र तथा सद्भावी व्यवहारियों से जो वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अन्तर्गत पंजीकृत हो से S.P.P.P पोर्टल पर प्रकाशित होने अथवा दिनांक 25.05.2026 से 02.06.2026 तक 01:00 पीएम तक बोली प्रपत्र विक्रय किए जाकर, दिनांक 03.06.2026 को प्रातः 09:00 एएम तक मोहरबन्द बोली RTPP एक्ट-2012 एवं RTPP नियम-2013 में निहित प्रावधान एवं GF&AR पार्ट-II के एस. आर. प्रारूप-16 की यथा उपान्तरित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती हैं एवं प्राप्त बोलियाँ दिनांक 03.06.2026 को समय 12:30 पीएम पर जिला न्यायालय अथवा अध्यक्ष, उपापन समिति के अवकाशागार में उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

क्र. सं.	उपापन की विषयवस्तु का विवरण स्पेसिफिकेशन	मात्रा	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति (EMD) राशि 2%	बोली प्रपत्र शुल्क	आपूर्ति अवधि	बोली विक्रय अवधि	बोली प्राप्ति दिनांक एवं समय अवधि	प्राप्त बोलियाँ खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	विभिन्न फर्नीचर मर्दे (बुडन एवं स्टील) स्पेसिफिकेशन बोली प्रपत्र के अनुसार	बोली प्रपत्र में अंकित अनुसार	6,48,000/-	12960/-	500/-	30 दिन	S.P.P.P पोर्टल पर प्रकाशित होने अथवा 25.05.26 से 02.06.26 (1 PM तक)	03.06.26 को 9:00 ए.एम. तक	03.06.26 को 12:30 पी.एम. पर

आवश्यक शर्तें:-

- बोली प्रतिभूति राशि का डी. डी. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के नाम से/पक्ष में देय होगा।
- बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष क्रय समिति/क्रेता अधिकारी को रहेगा।
- बोली से सम्बंधित विस्तृत शर्तें एवं विनिर्देश कार्य दिवसों में क्रेता के कार्यालय में तथा राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://www.sppp.rajasthan.gov.in>(UBN No.) पर एवं विभागीय वेबसाइट <http://www.kota.dcourts.gov.in> पर देखी जा सकती है।
- बोली प्रपत्रों का विक्रय, गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST) के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध करवाने पर ही किया जावेगा तथा सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
- बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि को सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश पड़ने पर बोली अगले कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार बोली खोलने की तिथि पर अवकाश घोषित हो जाने पर बोलियाँ अगले कार्य दिवस को तय समय पर खोली जावेगी।

कृ.पू.उ.

राजस्थान लोक उपापन समिति
का.नं. जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा (राजस्थान)

अन्य शर्तें:-

1. बोलियाँ विहित बोली प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएंगी, जिसे इस कार्यालय से नकद 500/- रूपए भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा। RTPP नियम 45(1) के अनुसार बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर इसकी कीमत का संदाय भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के पक्ष में डी.डी. द्वारा किया जा सकेगा। इस राशि का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो बोलियाँ विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी व नामंजूर करने योग्य होगी।
2. बोलियाँ मोहरबन्द लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से कोटा न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालयों अतिरिक्त सिविल न्यायालय एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा, एवं सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला कोटा के उपयोग हेतु "नवीन फर्नीचर" क्रय एवं बोली आमंत्रण सूचना संख्या" लिखा होगा, जो तय दिनांक व समय तक पहुँच जानी चाहिए। रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित निविदा के विलम्ब के लिए निविदादाता फर्म ही उत्तरदायी रहेगी।
3. जो भी बोलियाँ विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होंगी, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।
4. सामान/सामग्री को जिला न्यायालय परिसर या वांछित आपूर्ति स्टेशनों (इटावा एवं सांगोद मुख्यालय) तक पहुँचाने का लगेज/परिवहन व्यय एवं इन्स्टॉलेशन चार्ज अलग से देय नहीं होगा।
5. माल की आपूर्ति अनुमोदित स्पेसिफिकेशन एवं मेक के अनुसार करनी होगी अन्यथा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. उपापन समिति द्वारा आईटम्स वाईज निर्णय लिया जावेगा एवं दरें स्वीकृत होने के पश्चात् निविदा में उद्धृत मात्रा से कम-ज्यादा आईटम क्रय का अधिकार उपापन समिति के पास निहित रहेगा।
7. उद्धृत दर में GST व अन्य सभी प्रभार/शुल्क सम्मिलित होंगे तथापि अलग से देय नहीं होंगे।
8. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन एवं अनुमोदित नमूनों के अनुरूप आपूर्ति का प्रभारी अधिकारी (स्टोर) के सत्यापन एवं संचालन के बाद ही ECS/NEFT पद्धति से भुगतान सम्बन्धित न्यायालयों अतिरिक्त सिविल न्यायालय एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा, एवं सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला कोटा के लेखाशीर्षक की विस्तृत इकाई-05 कार्यालय व्यय में बजट उपलब्धता के अधधीन फर्म के बैंक खाते में अन्तरित किया जाएगा।
9. निविदत्त दरें निविदा खोलने की तिथि से 90 दिन तक वैध रहेंगी।
10. बोली शर्तों के किसी भी प्रकार के संदेह अथवा मन्शा के सम्बंध में बोली प्रपत्र खरीदने/डालने से पूर्व कार्यालय समय में क्रय समिति से स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है।
11. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र कोटा ही होगा।



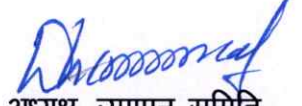
अध्यक्ष, उपापन समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

क्रमांक : प-जि.न्याया./लेखा/नवीन क्रय/फर्नीचर/2026-27/12797-12819 दिनांक : 22/05/2026
प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राजस्थान) को उनसे प्राप्त बजट आवंटन पत्र क्रमांक 1253-65 दिनांक 08.05.2026 के अनुसरण में।
2. निदेशक, निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (सचिवालय परिसर), जयपुर।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को उक्त बोली आमंत्रण सूचना विज्ञप्ति, बोली प्रपत्र एवं बोली शर्तें राजस्थान लोक उपापन पोर्टल की वेबसाइट <http://www.sppp.rajasthan.gov.in> पर एवं जिला न्यायालय की विभागीय वेबसाइट <http://www.kota.dcourts.gov.in> पर अविलम्ब प्रकाशित कर, पुष्टि उपलब्ध करवाने हेतु।
4. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बूंदी/बारों/झालावाड़ को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करवाने हेतु।

5. नोटिस बोर्ड कार्यालय सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी/नगर विकास न्यास/नगर निगम/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, कोटा (राजस्थान)।
6. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा।
7. सम्बन्धित न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायालय एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा, एवं सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला कोटा
8. नोटिस बोर्ड, अधीनस्थ न्यायालय-रामगंजमण्डी/ इटावा/ सांगोद/ कनवास/ दीगोद/ खैराबाद (कोटा)
9. रोकड़िया, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को बोली प्रपत्रों का निर्धारित तिथि तक विक्रय कर, प्राप्त राशि को लेखाशीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा करवाने हेतु।
10. ज्ञात फर्म मैसर्स

.....



अध्यक्ष, उपापन समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

बोली प्रपत्र

[RTPP का नियम-36(2)]

बोली प्रपत्र शुल्क 500/-

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 01/2026-2027

- कार्य का नाम— कोटा न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालयों अतिरिक्त सिविल न्यायालय एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा, एवं सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला— कोटा के उपयोग हेतु विभिन्न नवीन फर्नीचर मदों का उपापन
- बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम —
- बोली प्रपत्र शुल्क की राशि 500/- नकद रसीद संख्या..... दिनांक..... द्वारा जमा करा दी गई है।
- बोली प्रतिभूति (EMD) राशि 12960/- जमा का बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... बैंक का नाम..... का सलंगन कर दिया है।
- बोली में अंकित सामानों का अनुमानित मूल्य 6,48,000/- रुपये है।
- फर्म द्वारा आदेश प्राप्ति की दिनांक से 30 दिन की अवधि में माल की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।
- दरें दिनांक 31.03.2027 तक के लिए विधि मान्य हैं, इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
- फर्म का आयकर/जीएसटी नं..... है।
- क्रय किए जाने वाले आईटम सलंगन प्रपत्र के अनुसार हैं। आईटम के सामने फर्म द्वारा दरें अंकित की गई हैं जिसमें समस्त कर/जीएसटी शामिल है।
- हम जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना संख्या 01/2026-2027 दिनांक में वर्णित सभी शर्तों तथा सलंगन शीट में दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तों विनिर्देश से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। जिसको स्वीकर करने के प्रमाण में इनके सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

घोषणा पत्र

[GF&AR Part-II का नियम-48(vii)&RTPP नियम 39(4)] एस.आर. प्ररूप-11

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोटा का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा जिन मालों / सामानों / उपकरणों के लिए निविदा की गई है उसके हम बोनाफाईड विनिर्माता / थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/विपणन एजेंट है। राज्य सरकार/बोर्ड/ विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय सील) कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कारवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक:-

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर
पूर्ण पता व टेलिफोन न.

Dharmraj
 जयपुर जिला न्यायालय
 जयपुर, जिला एवं न्यायाधीश
 जयपुर (राज.)

कार्यालय—जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

बोली दस्तावेज मूल्य 500/- रुपये

बोली प्राप्ति दिनांक 03.06.2026 को समय 09:00 ए.एम. तक

बोली खोलने की दिनांक 03.06.2026 को समय 12:30 पी.एम. पर

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 01 / 2026—2027

बोली (निविदा) प्रपत्र (विशिष्टियाँ)

क्र० सं०	नाम सामग्री	विशिष्टियां (Specification)	मात्रा	अनुमानित राशि	निविदत दर प्रति नग(मय जीएसटी)	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सोफा सेट (3+2 Seater)	सोफा सेट 3+2 Seater sofa fully covered with Jute Fabric cloth with 40 density cushion. Size long piece (72"W x 16"H x 34"Back x 26"Depth), Size 2 Seater single piece (42.12"W x 16"H x 34"Back x 26"Depth)	2	52000/-		
2	सेन्टर टेबिल (वुडन)	सेन्टर टेबिल (लेमिनेटेड बोर्ड) Size 48"x24"x19" made of 17 mm laminated board, top with plain glass & four steel legs.	2	16000/-		
3	एकजीक्यूटिव चेयर चेम्बर (रिवाल्विंग)	चेम्बर चेयर Executive Revolving Chair 360 ° Revolving type, five revolving wheelsbase with P.U. arms. Seat size 20"x 20" High Back 20"x30" foam seat 40 density and back foam 32 density Iron base with quality pipe with chrome polished & Hydroliclifting syste in standard.	2	24000/-		
4	ऑफिस चेयर्स (बिना आर्म)	ऑफिस चेयर seat & back cushion having black ragzine frame will be M.S. pipe with chrome finished. (Seat 17"x18", back 16"x13")	20	51600/-		
5	विजीटर चेयर (स्टील पाईप फ्रेमड मय आर्म)	विजीटर चेयर (विद आर्म) with steel pipe framed having letherite seat & steel pipe arm with plastic cover.seat size 20"x19"back size 18"x24"	28	81200/-		
6	डायस चेयर (वुडन)	कोर्ट चेयर वुडन (पीठासीन अधिकारी) Teak wood framed with arm, seat 20"x 21 " & back 54" from bottom with foam seat&back 40 density, polish colour	2	20000/-		
7	ऑफिस टेबल (लेमिनेटेड बोर्ड) 4'x2½'x2½'H'	Size 4'x2½'x H2½' Office table with 17 mm laminated board, top size 4'x30" having teak wood beading, made of Iron Frame M.S. Pipe 1"x 1 " , Legs of Table Frame M.S. Pipe 2"x 1 " ,one side three drawer with smooth locking arrangement system.	24	114000/-		

बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

लगातार

बोली (निविदा) प्रपत्र (विशिष्टयाँ)

क्र० सं०	नाम सामग्री	विशिष्टियाँ (Specification)	मात्रा	अनुमानित राशि	निविदत दर प्रति नग(मय जीएसटी)	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
8	स्टील अलमारियां (size 1980x910x480) Approx. 60 kg wt	अलमारियाँ (स्टील) Size 1980x910x 480mm with 4 shelves having central locking arrangement system including redoxide primer&painting M.S. Sheet 20 gauze door &rest body 22 gauze (Approx. weight 60 kg)	16	157600/-		
9	बेन्च (पाईप फ्रेम व टॉप लेमिनेटेड बोर्ड) 5'x15"x18H"	size 5'x15"x18" with laminated top having 1" square 18 gauze pipe framed including painting.	4	8000/-		
10	स्टूल (पाईप फ्रेम व टॉप लेमिनेटेड बोर्ड)	स्टूल Size 1'x1'xH 1½ ' four legs, made of square 1"x1"pipe in 18 gauze&laminated top size 1'x1' & pipe frame painted.	12	6600/-		
11	बुक रेक्स (स्टील विद-आउट ग्लास शटर)	बुक रेक्स (लाईब्रेरी) Size 66"x33"x13" made of M.S. Sheet 22 gauze, 4 compartment including redoxide primer& oil painting.	4	28000/-		
12	एकजीक्यूटिव चेम्बर टेबल (लेमिनेटेड बोर्ड) Size 6' x 4' x 2)	चेम्बर टेबल (लेमिनेटेड बोर्ड) Size 6' x 4' x 2½' made of 17 mm laminated board, three side covered, one side one drawer & one box with drawer & one side three drawer at seating side with locking arrangement system & TOP "D" pattern good looking.	2	25000/-		
13	डायस टेबिल (वुडन)	डायस टेबिल (टीक वुडन) Size 6'x 4 x 2½' made of teak wood framed top 12 mm ply board with 1 mm mica, with 2 small drawer including text wood bidding, legs size 3"x3" with polish dark colour with separte foot rest. (Brown polish&brown mica)	2	36000/-		
14	वेटिंग स्टील चेयर	कुर्सी केनिंग(Half arm) Seat back canning half arm chair with 1" round 16 gauze pipe fully oil painted seat 17"x14.5", back 17"x12", final Height 18".	4	8000/-		
15	रेक्स (स्टील)	Size 78" x 36" x 16" Made of M.S. Sheets 20 gauze, 6 shelves making 5 compartment with heavy sloted angle of 40 x 45 x 3 mm including redoxide primer & oil painted.	8	20000/-		
TOTAL				648000/-		

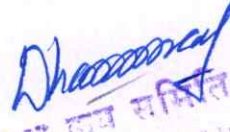
नोट :

- ओवरराईटिंग नहीं करें। कटिंग पर हस्ताक्षर करें।
- समस्त मदों की दरें अंकों और शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक मद की बोली केवल एक ही दर अंकित करना आवश्यक है। अन्यथा स्थिति में एक से अधिक दर अंकित होने पर केवल न्यूनतम दर ही स्वीकार्य होगी।
- यदि आइटम किसी ब्रांड/Make से सम्बन्धित होने पर, दर के समर्थन में आइटम का मेक (Make) व ब्रोशर भी संलग्न किया जावे।
- दर प्रस्ताव बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के अध्यक्षीन प्रस्तुत की गई है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 01/2026-27

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की आवश्यक शर्तें


उद्योग एवं सार्वजनिक
कोटा (राज०)
एस.आर.प्रारूप-16
[GF&ARपार्ट-II का नियम-68(3)]

[RTTP का नियम-36(3)]

- 1- बोली विहित प्रारूप-में प्रस्तुत की जावेगी। जिन्हे इस कार्यालय से 500/- रुपये नकद जमाकर प्राप्त किया जा सकता है। RTTP नियम 45(1) के अनुसार बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर इसकी कीमत का संदाय भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ "जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा" के पक्ष में डी. डी. द्वारा किया जा सकेगा। यह राशि प्रतिदाय नहीं होगी।
- 2- बोली बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "कोटा न्यायक्षेत्र के नवसृजित न्यायालयों अतिरिक्त सिविल न्यायालय एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा, एवं सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला कोटा के लिए विभिन्न नवीन फर्नीचर मदों का उपापन" हेतु बोली एवं बोली आमंत्रण सूचना संख्या व दिनांक लिखा होना चाहिए।
- 3- बोली दिनांक 03.06.2026 को समय प्रातः 9:00 बजे तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। बोली दिनांक 03.06.2026 को दोपहर 12:30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
- 4- न्यूनतम दरें वाली बोली को स्वीकार करने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगी तथा किसी भी बोली को या उस बोली के किसी भाग को बिना कारण बताएँ रद्द किये जाने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष (उपापन समिति) के पास सुरक्षित रहेगा।
- 5- विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 6- निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाईयों के द्वारा मूल पंजीयन प्रति या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करने पर उन सामानों के लिए, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है, बोली प्रतिभूति (EMD) राशि अनुमानित मूल्य का 0.5 प्रतिशत अथवा 1 प्रतिशत एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत अथवा 2 प्रतिशत यथासमय प्रभावी ली जावेगी। तथा उपरोक्त से भिन्न फर्मों के लिए बोली प्रतिभूति (EMD) राशि अनुमानित मूल्य का 2 प्रतिशत एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 5 प्रतिशत होगी।
- 7- वर्णित सामान की आपूर्ति बोली स्वीकार करने/कार्यादेश जारी करने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर की जावेगी। उक्त अवधि में करार निष्पादित करने की अवधि भी शामिल होगी। विहित परिदत्त अवधि में बोलीदाता जिन सामानों का प्रदाय करने में असफल रहेगा सा.वि.ले.नियम भाग-II के नियम-58(3) के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान (LD) की वसूली/कटौति की जावेगी तथा संविदा शर्तों को भंग करने की स्थिति में आरटीपीपी नियम-2013 के नियम-42 (11) के अनुसार बोली प्रतिभूति (EMD) राशि जब्त करने तथा नियम-76(3) में प्रावधानानुसार सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध आरटीपीपी अधिनियम-2012 या नियम-2013 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम या लाभप्रद बोली लगाने वाले को बोली स्वीकृति का प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र होगी।
- 8- बोली की मूल्यांकन कसौटी हेतु उपापन समिति द्वारा सामग्री क्रय एवं मात्रा का निर्णय गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन पूर्णता के आधार पर प्रत्येक आइटम वाईज वित्तीय परिणामों एवं नमूना परीक्षण पर आधारित होगा। उपापन समिति द्वारा सामग्री के भौतिक निरीक्षण/परीक्षण उपरान्त क्रय बाबत निर्णय लिया जावेगा। भौतिक परीक्षण हेतु सामग्री अन्दर 05 दिवस में (आइटम) जिला न्यायालय परिसर में फर्म को स्वयं के खर्च पर उपलब्ध/प्रस्तुत करवाना होगा। एतएव दर मूल्यांकन का विश्लेषण प्रत्येक आइटम वाईज अलग-अलग किया जावेगा। तथापि बोलीदाताओं से निविदत्त दर के समर्थन में उक्त फर्नीचर आइटम का मॉडल/नमूना सेम्पल उपलब्ध होने की अपेक्षा की जाती है।
- 9- उपापन समिति द्वारा जिन मदों को भौतिक निरीक्षण एवं परीक्षण के दौरान वांछित स्पेसिफिकेशन एवं मॉडल के अनुरूप अनुमोदित नहीं किया जावेगा, बोलीदाता अनुमोदित/स्वीकृत नहीं होने की सूचना प्राप्त होने पर अन्दर तीन दिवस में उक्त नमूना मदों को अपने स्वयं के खर्च पर हटा लेगा। इसके पश्चात् अस्वीकृत मदों की सुरक्षा/रख रखाव/टूट-फूट की जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। उपापन संस्था सेम्पल मदों को किसी भी रूप में लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी।
- 10- क्रय मदों का भौतिक परीक्षण प्रत्येक मद वाईज प्राप्त न्यूनतम वित्तीय दरों के अनुक्रम में यथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय लगातार क्रम में न्यूनतम दरदाता (L-1, L-2, L-3,.....) फर्मों से प्राथमिकता क्रम में किया जावेगा।

- 11- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना सेम्पल पर सेम्पल मद का नाम, साईज, समुचित स्पेसिफिकेशन, मेक, वजन तथा बोलीदाता फर्म का पूर्ण पता मय दूरभाष संख्या तथा सेम्पल प्रस्तुत करने की दिनांक व आवश्यक विवरण इत्यादि मजबूत कागज पर लिखकर सुरक्षित ढंग से बांधकर अथवा चिपकाकर, उसे उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जावेगा ताकि समान/समकक्ष सेम्पल से अदला-बदली नहीं हो सके।
- 12- परीक्षण हेतु प्रस्तुत नमूना सेम्पल मद की किसी भी प्रकार की क्षति, टूट फूट, जाँच के दौरान किसी भी हानि के लिए उपापन संस्था उत्तरदायी नहीं होगी।
- 13- निर्धारित अवधि के समाप्ति के बाद भी यदि असफल बोलीदाता अनुमोदित नहीं किए गए अपने नमूना सेम्पल प्राप्त नहीं करेगा अथवा नहीं हटायेगा तो उन्हें उपापन संस्था द्वारा समपहृत (Forefeit) कर लिया जावेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 14- न्यूनतम दरदाता फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में नमूना सेम्पल प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उसे असफल बोलीदाता घोषित किया जाकर अगले न्यूनतम दरदाता फर्म से नमूना सेम्पल प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जा सकेगा। यह क्रम अगले न्यूनतम दरदाता फर्म से निरन्तर अपनाया जावेगा।
- 15- दर स्वीकृति बाद आपूर्ति आदेश के अनुसार सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म अनुमोदित सेम्पल के अनुरूप उपापन मदों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा तथा आपूर्ति मदों की उचित पैकिंग स्वयं के खर्चे पर करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति/टूट-फूट नहीं हो तथा गन्तव्य स्थल पर उपापन संस्था को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। परिवहन के दौरान अथवा आपूर्ति प्राप्ति के समय किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, टूट-फूट या कमी होने पर, बोलीदाता फर्म उपापन संस्था को उन मदों की कमीपूर्ति/सुधार करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 16- यदि क्रय मदों की आपूर्ति उपापन संस्था की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जावेगी तो सम्बन्धित बोलीदाता (आपूर्तिकर्ता फर्म) को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद उपापन संस्था प्रदाय हेतु संविदा को किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकेगी, जो आपूर्तिकर्ता फर्म पर बाध्यकारी होगी।
- 17- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम-73 के अनुसार उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपापन नहीं करती है या बोली दस्तावेज में अंकित मात्रा से कम उपापन करती है तो बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त मदों या परिमाण के लिए पुनरादेश दिया जा सकेगा। पुनरादेश के लिए आपूर्ति अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश की मात्रा मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत तक होगी। यदि बोलीदाता, ऐसी सफ़लाई करने में असमर्थ रहता है तो उपापन संस्था अवशेष सामान की सफ़लाई कोटेशन/सीमित बोली पद्धति या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगी तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली की जावेगी।
- 18- सफल बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-
 - (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
 - (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास, कार्यालय व वर्कशॉप का पता व टेलीफोन/मोबाईल नम्बर।
 - (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- 19- बोली प्रतिभूति (EMD) राशि 12,960/- का बैंक ड्राफ्ट "जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा" के पक्ष में संलग्न करना होगा। इसके अभाव में प्रस्तुत बोली स्वीकार करने योग्य नहीं होगी तथा बोली प्रतिभूति RTPP नियम-42 (ii) के प्रावधानानुसार समपहृत (forfeited) के दायित्वाधीन होगी।
- 20- बोलीदाता को सामग्री की आपूर्ति जिला न्यायालय परिसर अथवा वांछित आपूर्ति स्टेशनों (इटावा एवं सांगोद मुख्यालय) पर करनी होगी।

- 21- किसी भी प्रकार का लगने वाला कर, जीएसटी, शुल्क स्वयं बोलीदाता द्वारा देय होगा। अतः **दरें समस्त कर व शुल्क सहित ही प्रस्तुत करनी होगी।** आवश्यक होने पर G.S.T. व T.D.S. की कटौती उपापन संस्था के स्तर पर की जाकर भुगतान किया जा सकेगा।
- 22- सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है अथवा किसी आइटम को क्रय करने/न करने के संबंध में क्रय समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
- 23- बोली की विधिमाम्यता अवधि आरटीपी नियम-2013 के नियम 48(1) के अनुसार **90 दिवस तक विधि मान्य रहेगी** किन्तु अपवादिक परिस्थिति में बोलीदाता की पारस्परिक सहमति से विधिमाम्यता अवधि अभिवृद्धि की जा सकेगी तथा बोली स्वीकृति के पश्चात् **अनुमोदित/स्वीकृत दर 31.03.2027 तक मान्य होगी।**
- 24- सफल बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना की तिथि से सात दिवस में **आरटीपीपीप नियम-70(7) सपठित 76(2) के अनुसार अपेक्षित मूल्य रुपये 500/- के न्यायिकेतर स्टॉम्प पर एस.आर.प्ररूप-17 में एक करार निष्पादित कर, कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि जयें ड्राफ्ट जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के पक्ष में जमा करवाना होगा।** कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा। **उक्त अवधि आपूर्ति अवधि 30 दिवस में ही शामिल रहेगी।** सामग्री की सफ़ाई संतोषजनक एवं नियत अवधि में नहीं होने की स्थिति में **जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि जब्त करने के दायित्वाधीन होगी।** कार्य सम्पादन प्रतिभूति सम्पूर्ण आपूर्ति बिना त्रुटिदायित्व के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने के पश्चात् दो माह में लौटाई जा सकेगी। **GF&ARपार्ट-II नियम 57(5)(ख)(i) व (ii) सपठित RTPP अधिनियम धारा 46(4) के प्रावधानान्तर्गत कार्य सम्पादन प्रतिभूति समपहत (Forfeited) के दायित्वाधीन होगी।**
- 25- यदि बोलीदाता द्वारा किसी अन्य विभाग/कार्यालय में बोली में अंकित सामग्री का निष्पादन किया गया हो तो ऐसे विभाग/कार्यालय के नाम भी प्रस्तुत किए जावें।
- 26- सफल बोलीदाता को सफलतापूर्वक आपूर्ति निष्पादित उपरान्त सम्बन्धित न्यायालयों अतिरिक्त सिविल न्यायालय एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा, एवं सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला कोटा के संबंधित बजट लेखाशीर्षकों की विस्तृत इकाई-05 कार्यालय व्यय (नवीन आईटम) में उपलब्ध बजट प्रावधानों के अध्याधीन भुगतान ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से बोलीदाता के खाते में अन्तरित किया जावेगा। जिसके लिए फर्म को पेन कार्ड बैंक खाता संख्या उपलब्ध करवाना होगा। भुगतान पर नियमानुसार आयकर (T.D.S.) देय होगा।
- 27- बोली स्याही या बालपेन या टंकण से भरी जावें। पेन्सिल से भरी बोलीपर विचार नहीं किया जावेगा, ओवर राईटिंग/कटिंग नहीं करें। ओवर राईटिंग/कटिंग होने पर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें।
- 28- सशर्त बोली प्रथमदृष्टया निरस्त योग्य होगी। बोलीदाता यदि ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो बोली में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उसके विरोध में है तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा।
- 29- आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं रूल्स 2013 व सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के समस्त प्रावधान उक्त क्रय पर यथा आवश्यक उपान्तरण सहित लागू एवं प्रभावी होंगे।
- 30- बोलीदाता को जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा बोली के साथ **GST रजिस्ट्रेशन व आयकर रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।** इसके अभाव में बोली स्वीकार करने योग्य नहीं होगी।
- 31- सभी मदों की दरें डालना अनिवार्य है। प्रत्येक आइटम की एकल दर ही मान्य होगी तथा एक से अधिक दर अंकित करने पर सम्बन्धित आइटम की न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी। जो फर्नीचर आइटम किसी ब्रान्ड/Make से सम्बन्धित होने पर, उसकी दर के साथ मेक अंकित कर ब्रोशर भी संलग्न किया जावे।
- 32- सा.वि.ले.नि. भाग-II के एस.आर. प्ररूप-16 एवं वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.2013 के संलग्नक (एनेक्चर ए से डी) की सम्पूर्ण शर्तें यथा उपान्तरित सहित उक्त उपापन पर प्रभावी रहेगी।
- 33- RTPP नियम-51 (2) के अनुसार बोली खोलने की तिथि को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने की स्थिति में बोली अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी।

- 34- अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जावेगा कि उसने प्रदाय करने वाली मर्दों के स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद ही दरें उद्यत की गई हैं। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, साईज, मॉडल आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो वह दर डालने व संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व क्रेता अधिकारी/उपापन संस्था से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।
- 35- राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-64 में प्रावधित प्रक्रियानुसार अंक गणितीय सुधार किया जा सकेगा।
- 36- अनुमोदित प्रदायकर्ता आपूर्ति आदेश के किसी भी भाग/मात्रा को किसी अन्य एजेंसी/फर्म को नहीं सौपेगा तथापि उप-भाड़े (सब-लेट) पर नहीं देगा।
- 37- प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएँ बोली में निर्धारित विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन) के मानकीकृत (स्टेन्डर्ड) के अनुसार अतिउत्तम गुणवत्ता एवं विवरण (Very best quality & description) के अनुसार होगी। इस बाबत उपापन संस्था द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम एवं सम्बन्धित बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।
- 38- जिन मर्दों पर वारंटी/गारंटी खन्ड लागू होगा उन मर्दों के लिए बोलीदाता इस आशय की गारंटी/वारंटी देगा कि गारन्टी/वारन्टी से सम्बन्धित विषयवस्तु/सामग्री सुपुर्दगी की दिनांक से विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी। इस तथ्य के बाद भी उक्त मर्दों के भौतिक निरीक्षण/परीक्षण पर उक्त विवरण एवं गुणवत्ता की नहीं होने पर उक्त मर्दों को उपापन समिति/उपापन संस्था को रद्द करने का हकदार होगा। रद्द की गई मर्दें सप्लायर/विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। सप्लायर को गारंटी/वारन्टी अवधि में जब भी ऐसा करने के लिए कहा जावेगा, वह उस माल/सामग्री को बदलने अथवा दोष सुधार करने के लिए तत्पर रहेगा, अन्यथा बोलीदाता ऐसी नुकसानी का भुगतान करेगा, जो इसमें दी गई गारन्टी/वारन्टी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी।
- 39- अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति (EMD)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) को नयी बोलियों (निविदाओं) के लिए बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति के प्रति समायोजित नहीं किया जावेगा। तथापि यदि बोलियों को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति को उपयोग में लिया जा सकेगा।
- 40- परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाय, टूट-फूट, रद्द की गई मर्दों/सामग्री के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जावेगी। कम सप्लाय, टूट फूट, रद्द किए गए सामानों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है, तो परिनिर्धारित क्षति के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध बोली कार्य सम्पादन प्रतिभूति से की जावेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत कार्यवाही कर वसूली की जावेगी।
- 41- करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा मूल प्रति प्रस्तुत की जावेगी।
- 42- वित्तीय बोली खोलने के बाद आवश्यकता हुई तो RTPP नियम 69 (2) के अनुसार न्यूनतम दरदाता से बातचीत (नेगोसिएशन) किया जा सकेगा। किन्तु नेगोसिएशन बोली लगाने वाले द्वारा दिये गए मूल प्रस्ताव को प्रभावहीन नहीं करेगी।
- 43- न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों से दरें असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में, बोली मूल्यांकन समिति न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों को एक लिखित प्रति प्रस्ताव देने का चयन कर सकेगी और यदि वह उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो उपापन समिति बोली को अस्वीकार करने तथा बोलियाँ पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है या वही प्रति प्रस्ताव दूसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले तथा अगले बोलीदाताओं को देकर, प्रदाय आदेश उस बोली लगाने वाले को अधिनिर्णित किया जा सकेगा, जो प्रतिप्रस्ताव स्वीकार करेगा।

- 44- आपूर्ति जब भी प्राप्त की जाएगी, उनका निरीक्षण/परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे वांछित स्पेसिफिकेशन या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहाँ आवश्यक एवं व्यवहारिक होगा परीक्षण उसके विषय विशेषज्ञ से करवाया जा सकेगा।
- 45- निरीक्षण एवं परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें निर्धारित अवधि में उसकी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
- 46- जहाँ सरकार कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से प्रश्नांकित मदों को बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जावेगा, तो उपापन संस्था बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेगी। इस प्रकार की गई कटौती अन्तिम होगी।
- 47- बोलीदाता को उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
- 48- उपापन समिति या उसका नामित प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर यथा आवश्यक होने पर प्रदायकर्ता के पसिरर/वर्कशॉप में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चित किया जाएगा, सभी युक्तियुक्त समयों पर क्रय मदों की सामग्री एवं कर्मकौशल (workmanship) का निरीक्षण एवं जाँच करने की सम्पूर्ण शक्तियाँ होगी।
- 49- RTPPNियम 51 (2) के अनुसार बोली प्राप्त करने या खोलने की तिथि को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने अथवा अंतिम तारीख कार्य दिवस नहीं होने की स्थिति में बोली अगले कार्य दिवस पर प्राप्त या खोली जावेगी।
- 50- समस्त बोलीदाताओं को इन शर्तों व विनिर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा बोली प्रस्तुत करते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना बोलीदाता पर बाध्यकारी है।
- 51- किसी भी प्रकार के विवाद में न्यायक्षेत्र कोटा शहर होगा।

सहमति स्वरूप बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म मोहर


अध्यक्ष (उपापन समिति)
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

एस.आर. प्ररूप-17
करार (अनुबंध) पत्र
(GF&ARपार्ट-II का नियम-68)/[RTPP का नियम-76(2)]
(निर्धारित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

Dharampal
अध्यक्ष जल संचित
कार्या. जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा (राज.)

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 01/2026-27

1. यह करार पत्र आज दिनांक माह सन् को
प्रथम पक्ष
..... (अनुमोदित सप्लायर) तथा राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जिला
एवं सेशन न्यायालय, कोटा द्वितीय पक्ष के मध्य सम्पन्न किया हुआ समझा जावेगा।
2. अनुमोदित सप्लायर
राजस्थान राज्य के जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा द्वारा जारी खुली निविदा सूचना संख्या 01/2026-27
दिनांक के अनुक्रम में प्रस्तुत कार्य/सामान
की निविदा के प्रतिफल में उक्त कार्यालय से प्राप्त कार्यालय/आपूर्ति आदेश क्रमांक
..... दिनांक राशि
..... अक्षरे में दी गई सभी वस्तुओं/सामानों की आपूर्ति निविदा एवं
संविदा की शर्तों पर दिये गये तरीके/प्रक्रिया से सरकार को करने के लिए सहमत हो गया हूँ।
3. उक्त कार्यादेश/आपूर्ति आदेश की राशि के पेटे @ 5 प्रतिशत
यथासमय प्रभावी दर से राशि की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD)
राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक से जमा
करवाई जा चुकी है।
4. यदि अनुमोदित सप्लायर कार्यादेश/आपूर्ति आदेश के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में कार्य/आपूर्ति करेगा,
उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाये रखेगा तो सरकार जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा के माध्यम
से राज्य सरकार की वित्तीय नीति निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माल प्रेषण की देय राशि का भुगतान करेगी या
करवाएगी।
5. माल की सुपुर्दगी कार्य आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक तक (अन्दर तीस दिवस) में
प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जावेगी।
6. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न
सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा द्वारा विनिश्चित किए जावेंगे जो अन्तिम रूप से
स्वीकार/मान्य होंगे।

निम्नांकित की साक्षी में दोनों पक्षकारों ने आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर किए।

प्रथम पक्षकार
(अनुमोदित सप्लायर का नाम एवं मोहर)

द्वितीय पक्षकार
(राज्यपाल की ओर से
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटा (राज.))

दिनांक :

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 2

साक्षी संख्या 2

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of bidder

Place:

Name :

Designation:

Address:

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

[See rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012**

Appeal No of

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

**3. Number and date of the order appealed against
and name and designation of the officer / authority
who passed the order (enclose copy), or a
statement of a decision, action or omission of
the Procuring Entity in contravention to the provisions
of the Act by which the appellant is aggrieved:**

**4. If the Appellant proposes to be represented
by a representative, the name and postal address
of the representative:**

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an
affidavit)

7. Prayer:

.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.


अध्यक्ष कम सचिव
कार्या. जिला एवं सदन न्यायाधीश
कोटा (राज.)